छत्तीसगढ़

डिजिटल विकास के साथ जड़ें मजबूत करना

संपादित : **सुषमा मिश्रा**

छत्तीसगढ़, जिसे अक्सर "भारत का धान का कटोरा" कहा जाता है, डिजिटल शासन और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में लगातार अग्रणी बनकर उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य ने अपनी मुख्यतः ग्रामीण और आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तकनीक का लाभ उठाया है, साथ ही सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की है।

भूमि अभिलेखों और धान खरीद के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण से लेकर डिजिटल छात्रवृत्ति, आधार-सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों तक की पहलों के साथ, छत्तीसगढ़ ने समावेशी विकास के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है। राज्य ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाहन, सारथी, एन.जी.डी.आर.एस., ई-कोर्ट, मनरेगासॉफ्ट और पीएमएवाई-जी जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों को भी एकीकृत किया है। एनआईसी, छत्तीसगढ़ ने राज्य विधानसभा में प्रश्न/उत्तर को और अधिक सहज बनाने के लिए भी तकनीक का लाभ उठाया है।

निकनेट, स्वान और एनकेएन के माध्यम से मजबूत नेटवर्क अवसंरचना द्वारा समर्थित और राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर व्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग द्वारा सुदृढ़, छत्तीसगढ़ एक डिजिटल रूप से सशक्त राज्य में परिवर्तित हो गया है। इसकी उपलब्धियों को

तेज नारायन सिंह
उप. महानिदेशक व एसआईओ
tnsingh@nic.in

सत्येश कुमार शर्मा
तकनीकी निदेशक व एसएमसी
satyesh@nic.in

ज्योति शर्मा
वैज्ञानिक - सी
jyoti.soni@nic.in

छत्तीसगढ़ भूमि अभिलेख (भुईंया, भू-नक्शा), कृषि (एकीकृत किसान पोर्टल, टोकन तुहार हाथ), कल्याण (छात्रवृत्ति पोर्टल, ए.ई.पी.डी.एस.), आवास, श्रम, उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में डिजिटल शासन के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। निकनेट, एनकेएन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहयोग से, राज्य राष्ट्रीय एमएमपी को एकीकृत करता है और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतता है। इसका भविष्य ऑटो-म्यूटेशन, एआई-संचालित एनालिटिक्स, पेपरलेस फाइनेंस और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुधारों में नवाचार के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, उसका ध्यान डिजिटल समावेशन को गहरा करने, एआई-संचालित विश्लेषण का विस्तार करने और नागरिक-केंद्रित पोर्टलों को बेहतर बनाने पर बना हुआ है - यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रौद्योगिकी शासन और जमीनी स्तर के बीच की खाई को पाटती रहे।

राज्य में आईसीटी पहलें

एनआईसी छत्तीसगढ़ शासन को बेहतर बनाने और नागरिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है। इसका ध्यान विभिन्न विभागों में एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल प्रणालियों के निर्माण पर रहा है। कुछ प्रमुख राज्य-स्तरीय आईसीटी पहलों में शामिल हैं:

भुइयां

https://bhuiyan.cg.nic.in

भुइयां छत्तीसगढ़ की प्रमुख भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण परियोजना है, जो कागज़-आधारित अभिलेखों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में परिवर्तित करती है। नागरिक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बी-I (खतौनी) और पी-II (खसरा) निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अधिकारी ओटीपी और आधार सत्यापन के साथ प्रविष्टियों, स्वचालित म्यूटेशन और अनुमोदनों का ऑनलाइन प्रबंधन करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ: ऑनलाइन नामांतरण रजिस्टर, जियो-टैगिंग के साथ मौसमी फसल (गिरदावरी) प्रविष्टि, आधार/मोबाइल लिंकेज, शहरी नजूल और डायवर्जन रिकॉर्ड, एसएमएस अलर्ट, और पटवारियों और नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप।

प्रभाव

- 20,527 गाँवों का डिजिटलीकरण; 19,566 मानचित्रों का एकीकरण
- 5,500 से अधिक पटवारी सक्रिय रूप से इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं
- बैंक एकीकरण से त्वरित कृषि ऋण प्राप्त होता है
- नागरिकों को भूमि अभिलेखों तक तत्काल, पारदर्शी पहुँच प्राप्त होती है।

स्वतः-म्यूटेशन के लिए एन.जी.डी.आर.एस. और योजना सत्यापन के लिए एकीकृत किसान पोर्टल से जुड़कर, भुइयां राज्य में डिजिटल भूमि प्रशासन की आधारशिला बन गया है।

भू-नक्शा

https://bhunaksha.cg.nic.in

भू-नक्शा छत्तीसगढ़ के भू-नक्शों को ऑनलाइन लाता है, जिसमें स्थानिक और पाठ्य भूमि अभिलेखों को एकीकृत किया गया है। यह भूखंडों के विभाजन, विलय और पुनर्संख्यांकन की सुविधा प्रदान करता है, और नामांतरण रजिस्टर में अद्यतनों को भी प्रदर्शित करता है।

मुख्य विशेषताएँ: 19,566 ग्राम मानचित्रों, क्षेत्रफल/दूरी मापन उपकरणों, स्वामी-वार भूखंड रिपोर्ट और कई मुद्रण विकल्पों (ए4 भूखंड मानचित्रों से ए0 ग्राम मानचित्रों) तक ऑनलाइन पहुँच। सुसंगतता के लिए सीधे भुइयां के साथ एकीकृत।

प्रभाव

- राज्य के लगभग सभी गाँवों का पूर्ण कवरेज
- 5,500 से अधिक पटवारी दैनिक कार्यों के लिए मानचित्रों को अद्यतन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं
- नागरिक भूमि भूखंड मानचित्रों को देख, डाउनलोड और प्रमाणित कर सकते हैं, जिससे विवादों में कमी आती है

भू-नक्शा भू-नक्शों को पाठ्य भूमि अभिलेखों के साथ जोड़कर, भू-नक्शा पारदर्शी, कुशल और नागरिक-अनुकूल भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

सी.जी.ए.डब्ल्यू.ए.ए.एस.

https://tcp.cg.gov.in

यह छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन प्रणाली है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कॉलोनी विकास परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करती है। यह बहु-विभागीय अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करती है।

मुख्य विशेषताएँ

- कॉलोनाइज़र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और डिजिटल भुगतान कर सकते हैं
- आवेदन निर्धारित समय-सीमा (120 दिन) के साथ नोडल विभागों में स्थानांतरित होते हैं
- आवेदकों को चरण-दर-चरण अपडेट, अस्वीकृति सूचनाएँ और अंतिम अनुमोदन डिजिटल रूप से प्राप्त होते हैं
- कॉलोनी अनुमोदन और राजस्व के लिए स्वचालित एमआईएस

प्रभाव (2025)

- 804 आवेदन प्राप्त हुए, 238 वितरित किए गए, और 29 खसरा एकीकरण पूर्ण हुए
- अनुमोदनों से ₹34.9 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ
- शहरी विस्तार के लिए मैन्युअल अड़चनों को कम किया गया और तेज़ निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई

कॉलोनी अनुमोदनों को डिजिटल बनाकर, सी.जी.डब्ल्यू.ए.ए.एस. ने तेज़ आवास विकास, बेहतर शहरी प्रशासन और डेवलपर्स और नागरिकों दोनों के लिए अधिक पारदर्शिता को सक्षम बनाया है।

ऑनलाइन ऑडिट और ई-सीएसए

https://res.cg.gov.in

छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन ऑडिट और ई-सीएसए (राज्य ऑडिट प्रणाली) प्लेटफ़ॉर्म पंचायती राज संस्थाओं, मंडियों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों और निगमों के ऑडिट को डिजिटल बनाते हैं, मानकीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

- पंचायती राज संस्थाओं का ऑनलाइन ऑडिट, ई-ग्राम स्वराज के साथ एकीकृत
- मंडियों, विश्वविद्यालयों और राज्य संस्थाओं के लिए कार्यप्रवाह-आधारित ऑडिट
- मानकीकृत प्रारूप, डिजिटल संरक्षण और एमआईएस डैशबोर्ड
- रीयल-टाइम फंड ट्रैकिंग के लिए ई-कोष और ई-वर्क्स से लिंक

प्रभाव

- 11,688 ग्राम पंचायत प्रोफाइल बनाए, जिनमें से 11,586 ग्राम विकास परियोजनाएँ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपलोड की गईं
- पंचायती राज संस्थाओं और संस्थानों में 11,800 से अधिक ऑडिट पूरे किए गए
- कई ई-पंचायत पुरस्कारों से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त

इन प्रणालियों ने रीयल-टाइम वित्तीय निगरानी को सक्षम बनाया है और फंड उपयोग में जमीनी स्तर पर जवाबदेही को मजबूत किया है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल

https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/

छत्तीसगढ़ का पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को छात्रवृत्ति का कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह वितरण सुनिश्चित करना है। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म छात्रवृत्ति प्रबंधन के संपूर्ण जीवनचक्र को सुव्यवस्थित करता है - छात्र पंजीकरण और छात्रावास नामांकन से लेकर धन स्वीकृति, हस्तांतरण और व्यय निगरानी तक। यह प्रणाली मैन्युअल बाधाओं को दूर करती है और छात्रावास अधीक्षकों, जिला अधिकारियों और राज्य प्रशासकों सहित हितधारकों को समन्वित और पारदर्शी तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाती है।

मुख्य विशेषताएँ

- **ऑनलाइन छात्रावास प्रबंधन:** नए प्रवेश, नवीनीकरण, उपस्थिति और वार्षिक छात्रावास बंद होने की संपूर्ण प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण
- **एकीकृत कार्यप्रवाह:** अधीक्षकों से लेकर सहायक आयुक्तों द्वारा जिला-स्तरीय अनुमोदन तक निधि प्रस्तावों को सुव्यवस्थित करना
- **डीबीटी:** कुशल और सुरक्षित भुगतान के लिए छात्रवृत्ति और वजीफे सीधे अधीक्षकों और प्रधानाध्यापकों के संयुक्त खातों में जमा करना
- **वास्तविक समय व्यय निगरानी:** छात्रावास/आश्रम निधियों पर वास्तविक समय में नज़र रखना, आवंटित निधियों की स्वीकृत बनाम स्वीकृत सीटों से तुलना करना
- **एमआईएस रिपोर्टिंग:** विभागीय अधिकारियों को सूचित योजना, लेखा परीक्षा और निर्णय लेने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रदान करना

प्रभाव और उपलब्धियाँ

- 1341 आश्रम, 1782 प्री-मैट्रिक छात्रावास और 457 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास इस प्रणाली पर पंजीकृत हैं
- चालू सत्र में 78,917 नए छात्र और 1,25,652 नवीनीकरण छात्र नामांकित हुए
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से छात्रावासों/आश्रमों को ₹301 करोड़ सफलतापूर्वक हस्तांतरित किए गए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई
- रीयल-टाइम डैशबोर्ड प्रशासकों को जिलों में छात्रावासों में उपस्थिति, स्वीकृत सीटों और व्यय के रुझान की निगरानी करने में सक्षम बनाते हैं

इस पोर्टल ने न केवल प्रसंस्करण में देरी और प्रशासनिक खर्चों को कम किया है, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के बीच विश्वास भी बढ़ाया है। सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों और लाभार्थियों के बीच की खाई को पाटकर, यह समावेशी शिक्षा के लिए डिजिटल सशक्तिकरण का एक मॉडल बन गया है।

एचएमएस और आर.एस.एम.आई.एस

छत्तीसगढ़ की छात्रावास प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) और आवासीय विद्यालय एमआईएस (आर.एस.एम.आई.एस), राज्य द्वारा संचालित छात्रावासों और विशिष्ट आदिवासी विद्यालयों के प्रशासन को डिजिटल बनाती हैं, जिससे छात्र कल्याण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

छात्रावास प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस)

- 1341 आश्रमों, 1782 प्री-मैट्रिक और 457 पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण
- छात्रावास अधीक्षकों द्वारा प्रस्तुत उपस्थिति, व्यय और निधि प्रस्तावों पर नज़र रखती है।
- स्वीकृत बनाम स्वीकृत सीटों की निगरानी के लिए डैशबोर्ड के साथ, जिला-स्तरीय सत्यापन के बाद सीधे निधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।

आवासीय विद्यालय एमआईएस

- 75 एकलव्य विद्यालयों (21,084 छात्र) और 15 प्रयास विद्यालयों (4,946 छात्र) को कवर करता है
- प्रवेश, आवधिक परीक्षा परिणाम और शैक्षणिक प्रदर्शन रिकॉर्ड करता है
- ऑनलाइन निधि स्वीकृति और उपयोग निगरानी के साथ, बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति संसाधनों पर नज़र रखता है।

ये प्रणालियाँ मिलकर छात्रों के प्रवेश, शैक्षणिक परिणामों और संसाधन प्रबंधन की निगरानी के लिए एक 360° डिजिटल ढांचा तैयार करती हैं। छात्रावास कल्याण को विद्यालय प्रदर्शन ट्रैकिंग के साथ जोड़कर, वे जनजातीय और हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने और लक्षित समर्थन सुनिश्चित करते हैं।

इन पोर्टलों को https://hmstribal.cg.nic.in/ और https://eklavya.cg.nic.in/ पर एक्सेस किया जा सकता है।

▼ चित्र 2.1 : माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साईं ने छत्तीसगढ़ भर में 51 महतारी सदनों का वर्चुअल उद्घाटन किया

एनआईसी ने हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली पोर्टल बनाया है। यह डिजिटल शासन में एक बड़ी सफलता है। इस पहल से पता चलता है कि हम हर छात्र को बराबर और हॉस्टल/आश्रम से जुड़ी अच्छी शिक्षा देने के लिए पक्के हैं।

यह पोर्टल नई तकनीक से हॉस्टल के सारे काम आसान बनाता है, जिससे सही छात्रों को पूरी पारदर्शिता, तेज़ी और सही समय पर मदद मिलती है। हमारा मानना है कि यह पोर्टल आगे चलकर सरकारी मदद देने के तरीके को और बेहतर बनाएगा, जिससे हमारे देश के युवाओं को शक्ति मिलेगी और देश का भविष्य मज़बूत होगा।

सोनमणि बोरा, आईएएस
प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग, छत्तीसगढ़

एकीकृत किसान पोर्टल

https://agriportal.cg.nic.in

एकीकृत किसान पोर्टल एक एकल-खिड़की प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रत्येक किसान को भुइयां भूमि अभिलेखों से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी प्रदान करता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और दोहराव समाप्त होता है।

मुख्य विशेषताएँ

- एक किसान - एक आईडी जिसमें व्यक्तिगत, भूमि और फसल संबंधी विवरण शामिल हैं
- धान खरीद, बागवानी, इथेनॉल और गन्ना खरीद, पीएम-आशा जैसी योजनाओं का समर्थन करता है
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए तैयार, बैंक खातों का सत्यापन पीएफएमएस के माध्यम से किया जाता है
- सुरक्षित अंतर-संचालन के लिए एपीआई-आधारित डेटा साझाकरण
- एकल पंजीकरण, अनेक योजनाओं में उपयोग योग्य

प्रभाव (2025)

- 27.19 लाख किसान पंजीकृत
- 207 फसलों और 37.2 लाख हेक्टेयर का मानचित्रण
- अनेक विभागों में निर्बाध लाभ वितरण
- दोहराव को रोका, दक्षता में सुधार किया, और वास्तविक समय निगरानी को सक्षम बनाया

यह पोर्टल छत्तीसगढ़ में डिजिटल कृषि शासन की रीढ़ बन गया है, जिसने किसानों की पहुँच को सरल बनाया है और डेटा-आधारित नीतिगत निर्णयों का समर्थन किया है।

कंप्यूटरीकृत धान खरीद प्रणाली

छत्तीसगढ़ ने 2007 में अपनी कंप्यूटरीकृत धान खरीद प्रणाली की शुरुआत की, जिसने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाते हुए 25.49 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया।

शुरुआती चरण में, अधिकांश केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी थी, इसलिए खरीद, मिलर को जारी करने और रसीदों को संभालने के लिए एक स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। अभिनव रनर्स मॉड्यूल के तहत लगभग 250 मोटरसाइकिल सवारों को तैनात किया गया, जो केंद्रों से ब्लॉक मुख्यालयों तक दैनिक डेटा ले जाते थे, जहाँ इसे एनआईसीनेट के माध्यम से अपलोड किया जाता था। सी.जी.एस.सी.एस.सी. और एफसीआई के सीएमआर केंद्र भी इसी तरह के ऑफ़लाइन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते थे जो सर्वर के साथ स्वतः सिंक हो जाता था। पूर्ण कंप्यूटरीकरण ने किसानों को चेक से तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया।

आज, सभी खरीद संचालन—मिल पंजीकरण, अनुमति, समझौते, प्रतिभूतियाँ, डिलीवरी ऑर्डर, और रसीदें/इश्यू—पूरी तरह से ऑनलाइन हैं। किसानों और मिलरों को भुगतान पी.एफ.एम.एस. और एसबीआई एसएफजी सर्वर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित किया जाता है।

खरीद टोकन के लिए लगने वाली कतारों को समाप्त करने के लिए, एनआईसी ने 'तुँहर टोकन' ऐप लॉन्च किया, जिससे किसान स्वयं टोकन जनरेट कर सकते हैं और केंद्र-वार विवरण की जाँच कर सकते हैं। समितियों के माध्यम से ऑफ़लाइन टोकन विकल्प अभी भी उपलब्ध हैं।

किसान पंजीकरण अब राष्ट्रीय एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पहले ही 26.49 लाख किसान एग्रीस्टैक आईडी के साथ यूनिफाइड फार्मर्स पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, और खरीद 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी।

मुख्य विशेषताएँ

- राज्य भर में 2,739 खरीद केंद्र
- 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद
- 87 भंडारण केंद्रों, 296 सीएमआर डिपो और 2,889 चावल मिलों के साथ एकीकृत
- 64% किसानों ने टोकन बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप का सक्रिय रूप से उपयोग किया

भूमि अभिलेख, बैंक खातों और उपार्जन डेटा के एकीकरण से छत्तीसगढ़ ने एक पारदर्शी, कुशल और किसान-हितैषी डिजिटल प्रणाली विकसित की है—जो डिजिटल कृषि प्रशासन का एक आदर्श मॉडल बन चुकी है।

ए.ई.पी.डी.एस और आर.सी.एम.एस.

https://epos.cg.gov.in/

आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एईपीडीएस) और राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) छत्तीसगढ़ की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का संपूर्ण स्वचालन प्रदान करती है, जिससे एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

- **व्यापक कवरेज:** 13,940 एफ़पीएस में 81 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक
- **आधार प्रमाणीकरण:** दोहराव को समाप्त करता है और वास्तविक लाभार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करता है
- **पोर्टेबिलिटी:** ओ.एन.ओ.आर.सी. के अंतर्गत किसी भी एफ़पीएस से राशन उपलब्ध है
- **रीयल-टाइम निगरानी:** डिजिटल पीओएस उपकरण एमआईएस डैशबोर्ड के लिए लेनदेन को रिकॉर्ड करते हैं
- **योजना-वार ट्रैकिंग:** एन.एफ.एस.ए., सी.जी.एफ.एस.ए., अंत्योदय और अन्य श्रेणियों का समर्थन करता है

प्रभाव

- 81.03 लाख कार्ड और 2.6 करोड़ से अधिक लाभार्थी
- सभी एफपीएस पर स्वचालित लेनदेन
- खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि

इस प्रणाली ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक नागरिक-केंद्रित, जवाबदेह और पोर्टेबल नेटवर्क में बदल दिया है, जिससे निवासियों और प्रवासी परिवारों दोनों को लाभ हो रहा है।

श्रम विभाग पोर्टल

https://shramevjayate.cg.gov.in/

छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग पोर्टल पंजीकरण, कल्याणकारी योजनाओं, उपकर संग्रह और अनुपालन निगरानी को एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करता है। यह श्रमिकों, नियोक्ताओं और ठेकेदारों के लिए संपूर्ण स्वचालन प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

- **श्रमिक पंजीकरण:** आधार-आधारित सत्यापन के साथ निर्माण, संगठित और असंगठित श्रमिकों को शामिल करता है
- **क्यूआर-कोडेड स्मार्ट कार्ड:** श्रमिकों को पहचान और योजना तक पहुँच के लिए जारी किए जाते हैं
- **ऑनलाइन उपकर और शुल्क संग्रह:** व्यापार में आसानी के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** छात्रवृत्ति, मातृत्व, पेंशन और आवास लाभ सीधे श्रमिक खातों में जमा किए जाते हैं
- **जोखिम-आधारित निरीक्षण:** पारदर्शिता के लिए स्वचालित ऑनलाइन निरीक्षण
- **एकल खिड़की:** नियोक्ताओं, ठेकेदारों, कारखानों और ट्रेड यूनियनों के लिए एकीकृत सेवाएँ

प्रभाव

- 49.3 लाख श्रमिक पंजीकृत (29 लाख निर्माण, 17 लाख असंगठित, 2 लाख संगठित)
- 20,426 नियोक्ता/ठेकेदार जुड़े
- ₹1,300+ करोड़ उपकर और ₹33+ करोड़ कल्याणकारी निधि प्रतिवर्ष एकत्रित
- 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) आधारित योजना लाभ प्राप्त हुए

पंजीकरण, योजना लाभ और अनुपालन को डिजिटल बनाकर, यह पोर्टल एक वन-स्टॉप श्रम शासन समाधान के रूप में उभरा है, जो श्रमिकों को सशक्त बनाते हुए उद्योग के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

ई-आवास

https://cghb.gov.in

ई-आवास प्रणाली छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाती है, जिससे आवंटन में पारदर्शिता और कुशल संपत्ति संचालन सुनिश्चित होता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **संपत्ति और लेखा प्रबंधन:** आवंटन, वसूली और वित्त के लिए कार्यप्रवाह-आधारित मॉड्यूल
- **ऑनलाइन संपत्ति खोज (समृद्धि):** नागरिक संपत्तियों की खोज, उपलब्धता की जाँच और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
- **डिजिटल भुगतान:** किश्तों और शुल्कों के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे
- **पारदर्शिता:** आवेदन से लेकर आवंटन तक डिजिटल ट्रैकिंग

प्रभाव

- हज़ारों संपत्ति आवेदनों का डिजिटल रूप से प्रसंस्करण
- कम कागजी कार्रवाई, तेज़ अनुमोदन और नागरिकों की सुविधा
- आवास बोर्ड के लेन-देन में जवाबदेही बढ़ी है

इस प्रणाली ने संपत्ति प्रबंधन को नागरिक-अनुकूल, पारदर्शी और पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया में बदल दिया है।

ई-आबकारी

https://excise.cg.nic.in

छत्तीसगढ़ की ई-आबकारी परियोजना एक अग्रणी पहल है जो लाइसेंस जारी करने से लेकर आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग, राजस्व संग्रहण और प्रवर्तन तक संपूर्ण आबकारी मूल्य श्रृंखला को कवर करती है

मुख्य विशेषताएँ

- **एंड-टू-एंड ऑटोमेशन:** लाइसेंस/परमिट/एनओसी जारी करना, नवीनीकरण और अनुमोदन ऑनलाइन।
- **आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग:** शराब की सूची के लिए बारकोडिंग और क्यूआर कोडिंग; जीपीएस-सक्षम वाहन ट्रैकिंग।
- **राजस्व संग्रहण:** ऑनलाइन आबकारी शुल्क संग्रहण, नकद प्रबंधन और वास्तविक समय निगरानी।
- **प्रवर्तन और पारदर्शिता:** आर.एफ.आई.डी.-सक्षम नकदी ट्रैकिंग, सी.सी.टी.वी. एकीकरण और यादृच्छिक निरीक्षण।
- **मोबाइल ऐप्स:** बार मालिकों, स्टॉक ऑर्डरिंग और कर्मचारी उपस्थिति (ए.ई.बी.ए.एस.) के लिए।

प्रभाव

- 43,1585 परमिट और 61,586 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी
- डिजिटल माध्यमों से ₹40,271 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ
- परिवहन वाहनों में 520 जीपीएस उपकरण लगाए गए और 100 से अधिक निगरानी कैमरे लगाए गए
- नकदी प्रबंधन के लिए 530 आर.एफ.आई.डी. कार्ड जारी किए

हर कदम को डिजिटल बनाकर, ई-आबकारी ने छत्तीसगढ़ को आबकारी प्रशासन में भारत के सबसे उन्नत राज्यों में से एक बना दिया है, जिससे पारदर्शिता, उच्च राजस्व और सख्त अनुपालन सुनिश्चित हुआ है।

विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली

https://igkv.ac.in

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आई.जी.के.वी.) में विश्वविद्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली एक संपूर्ण स्वचालन प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रवेश, शैक्षणिक, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान और डिजिटल लाइब्रेरी सेवाओं को कवर करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- **प्रवेश एवं शैक्षणिक:** ऑनलाइन आवेदन, ओएमआर-आधारित परीक्षाएँ, शिकायत निवारण और परिणाम प्रसंस्करण।
- **वित्त एवं मानव संसाधन:** कम्प्यूटरीकृत बिल स्वीकृति, पेरोल, सेवा पुस्तिकाएँ और सीआर प्रबंधन।
- **भर्ती:** प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती।
- **डिजिटल पुस्तकालय एवं अनुसंधान:** आई.जी.के.वी. वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध निष्कर्षों और नवाचारों तक सीधी पहुँच।
- **मोबाइल ऐप्स:** क्रॉप डॉक्टर, ई-कृषि पाठशाला, ई-हाट और किसानों के लिए कस्टम हायरिंग।

प्रभाव

- 2,000 से अधिक आवेदनों का डिजिटल रूप से निपटाया गया
- 9.6 लाख किसानों के प्रश्नों का समाधान किया गया।
- 4.4 लाख वित्तीय बिल तैयार किए गए।
- कृषि परामर्श और मशीनीकरण सेवाओं के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ।

इस प्रणाली ने आई.जी.के.वी. को एक डिजिटल रूप से सक्षम कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया है, जो शिक्षाविदों, प्रशासन और किसानों तक पहुँच को एक मंच पर जोड़ता है।

स्वास्थ्य सेवा आईटी प्रणालियाँ

छत्तीसगढ़ ने अस्पताल स्वचालन, स्वास्थ्य कर्मियों के भुगतान, मातृ देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को आईसीटी प्लेटफार्मों में एकीकृत करके एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। ये पहलें यह सुनिश्चित करती हैं कि स्वास्थ्य सेवा वितरण कुशल, जवाबदेह और सुलभ हो, खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल

https://nextgen.ehospital.gov.in

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली एक संपूर्ण अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.) है जो राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में स्थापित है। यह मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है।

- **विशेषताएँ:** आभा से जुड़ा ओपीडी/आईपीडी पंजीकरण, टोकन और कतार प्रबंधन, ई-प्रिस्क्रिप्शन, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, ओटी शेड्यूलिंग, लैब एकीकरण, बिलिंग और डिस्चार्ज।
- **प्रभाव:** 306 अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज आदि शामिल हैं, जिससे सुचारू कार्यप्रवाह और तेज़ रोगी देखभाल सुनिश्चित हुई है।

एनएचएम डीबीटी पोर्टल

https://nhmdbt.cg.nic.in

एनएचएम डीबीटी पोर्टल अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को समय पर प्रोत्साहन भुगतान सुनिश्चित करता है।

- **कवरेज:** 33 जिलों और 21,000 गाँवों में 71,000 से अधिक मितानिनें और 3,000 प्रशिक्षक शामिल हैं।
- **प्रभाव:** ₹40 करोड़ से अधिक का मासिक डीबीटी, सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को मज़बूती मिलती है।

राज्य स्वास्थ्य प्रणालियाँ

- **उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था निगरानी:** समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए मातृ स्वास्थ्य पर नज़र रखता है।
- **सीएम हाट बाज़ार क्लीनिक:** मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ साप्ताहिक आदिवासी बाज़ारों में सेवाएँ प्रदान करती हैं, दूरस्थ आबादी तक पहुँचती हैं।
- **एस.ओ.टी.टी.ओ. (राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन):** अंग और ऊतक दान की निगरानी करता है, पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करता है।
- **स्वास्थ्य इन्वेंट्रैक:** दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करता है।
- **ई-कल्याणी:** एमटीपी अधिनियम के अनुपालन के लिए गर्भपात सेवाओं की ऑनलाइन निगरानी।
- **पोषण पुनर्वास केंद्र:** गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से ग्रस्त 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की डिजिटल निगरानी।

लाभ

- **नागरिकों के लिए:** स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच, कम प्रतीक्षा समय और बेहतर मातृ एवं शिशु देखभाल।
- **स्वास्थ्य कर्मियों के लिए:** समय पर भुगतान, बेहतर निगरानी और कम प्रशासनिक बोझ।
- **प्रशासन के लिए:** रीयल-टाइम डैशबोर्ड, बेहतर निधि उपयोग और डेटा-आधारित नीति नियोजन।

इन आईसीटी प्रणालियों ने मिलकर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवा को एक डिजिटल रूप से सक्षम, नागरिक-केंद्रित नेटवर्क में बदल दिया है, जिससे शहरी अस्पतालों और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों, दोनों में समान पहुँच सुनिश्चित हुई है।

अन्य राज्य स्वास्थ्य प्रणालियाँ

- **राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण:** मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और निगरानी को विनियमित करता है
- **ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस एमआईएस:** आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का रिकॉर्ड रखता है
- **राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम:** रोकथाम और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए किफायती मुख स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करता है
- **छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड:** दवाओं, शल्य चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद और वितरण
- **स्वास्थ्य डैशबोर्ड (बजट और योजनाएँ):** बेहतर योजना के लिए धन आवंटन/उपयोग और योजना की प्रगति की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है।

ये सभी पहल मिलकर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल रूप से सक्षम, समावेशी और नागरिक-अनुकूल बनाती हैं, जिससे नीति और अंतिम छोर तक पहुँच के बीच की खाई को पाटा जा सकता है।

राज्य में कार्यान्वित केंद्रीय परियोजनाएँ

छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) को अपनाने और लागू करने में सक्रिय रहा है, और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हुए नागरिकों की सुविधा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है।

▼ चित्र 2.2 : कागज रहित शासन के लिए पुलिस कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर प्रशिक्षित किया गया

वाहन 4.0 और सारथी 4.0

वाहन 4.0 और सारथी 4.0 सभी 28 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पूरी तरह से लागू हैं। ये वाहन पंजीकरण, परमिट, कर संग्रह, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस /लर्निंग लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और स्वामित्व हस्तांतरण के लिए फेसलेस, पेपरलेस सेवाएँ प्रदान करते हैं। राज्य अब 33 फेसलेस वाहन सेवाएँ और 24 फेसलेस सारथी सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे आरटीओ में आने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

वाहन के माध्यम से 90 लाख से अधिक वाहनों से संबंधित 2 करोड़ लेनदेन संसाधित किए गए हैं, जिनका मूल्य ₹13,000 करोड़ है। सारथी ने 36 लाख ड्राइविंग लाइसेंस और 23 लाख लर्निंग लाइसेंस जारी किए हैं, जिससे ₹311 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए, 555 परिवहन सेवा केंद्र और 238 पीयूसीसी केंद्र (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र केंद्र) कार्यरत हैं।

एचएसआरपी फिक्सेशन दो वेंडरों की तैनाती के साथ जिलों में अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। वी.एल.टी.डी प्रणालियाँ, 8 स्वचालित परीक्षण स्टेशन , आई.आर.ए.डी , और दो स्मार्ट शहरों में आई.टी.एम.एस पूरी तरह से कार्यशील हैं।

वी-कोर्ट 45/90 दिनों के बाद भुगतान न किए गए चालानों को स्वचालित रूप से संसाधित करता है, जिसकी चालान संबंधी जानकारी एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। एएनपीआर और टोल प्लाजा कैमरों का उपयोग करके ई-डिटेक्शन स्वचालित प्रवर्तन सुनिश्चित करता है।

स्वच्छ गतिशीलता की ओर राज्य के प्रयास को मजबूत करते हुए, एक ईवी सब्सिडी पोर्टल भी कार्यशील है।

एन.जी.डी.आर.एस.

एन.जी.डी.आर.एस. (राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली) परियोजना एक राष्ट्र, एक पंजीकरण ढांचे के तहत डिजिटल संपत्ति पंजीकरण और नामांतरण को सक्षम बनाती है।

- **कवरेज:** छत्तीसगढ़ के सभी 102 उप-पंजीयक कार्यालयों में कार्यान्वित
- **एकीकरण:** वास्तविक समय सत्यापन और स्वचालित नामांतरण के लिए भुइयां (भूमि अभिलेख) से जुड़ा
- **लाभ:** नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज़ तैयार, जमा और ट्रैक कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी और देरी कम होती है

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल

राज्य के 306 सरकारी अस्पतालों में स्थापित, नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली अस्पताल के कार्यप्रवाह का संपूर्ण स्वचालन प्रदान करती है।

- **विशेषताएँ:** ओपीडी/आईपीडी पंजीकरण, एबीएचए एकीकरण, निदान, फार्मेसी और बिलिंग
- **प्रभाव:** 2.16 करोड़ से ज़्यादा ओपीडी पंजीकरण और 14.6 लाख आईपीडी मामले डिजिटल रूप से दर्ज किए गए, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण में दक्षता में सुधार हुआ

सी.सी.एम.एस

सी.सी.एम.एस छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध दायर किए गए अदालती मामलों की शुरुआत से लेकर निपटान तक निगरानी के लिए एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है। यह मामला डेटा को केंद्रीकृत करता है, फाइलिंग से लेकर निपटान तक की कार्यवाही को ट्रैक करता है, और समय पर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय के अपडेट, डैशबोर्ड और स्वचालित रिपोर्ट प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- वास्तविक समय में मामलों के सिंक्रनाइज़ेशन के लिए नेपिक्स–एनजेडीजी एकीकरण
- भूमिका-आधारित डैशबोर्ड और अनुकूलन योग्य एमआईएस रिपोर्ट
- सभी लंबित और निपटाए गए मामलों का केंद्रीकृत भंडार
- जवाब, अनुपालन और समय-सीमा की स्वचालित ट्रैकिंग
- सुनवाई और अनुपालन के लिए एसएमएस अलर्ट
- किसी भी समय मामलों तक पहुँच के लिए मोबाइल ऐप

प्रभाव (2025):

- 45 विभागों में 3,206 उपयोगकर्ताओं द्वारा 77,038 मामलों की डिजिटल रूप से निगरानी की गई
- स्वचालित अलर्ट के माध्यम से तेज़ अनुपालन
- वास्तविक समय डेटा से शासन और समन्वय में सुधार
- डिजिटल वर्कफ़्लो के माध्यम से कागज़ी कार्रवाई में कमी

आई.सी.जे.एस.

छत्तीसगढ़ ने अपने न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय आईसीजेएस (इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत किया है, जिसमें ई-कोर्ट, ई-फ़ोरेंसिक, ई-अभियोजन, ई-कारागार और ई-समन शामिल हैं।

- **लाभ:** पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और फ़ोरेंसिक विभागों के बीच निर्बाध डेटा आदान-प्रदान संभव
- **प्रभाव:** तेज़ जाँच, बेहतर केस ट्रैकिंग और न्याय हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय

आई.वी.एफ.आर.टी.

आई.वी.एफ.आर.टी. (अप्रवासन, वीज़ा और विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग) परियोजना सभी जिला-स्तरीय विदेशी पंजीकरण कार्यालयों (एफआरओ) में लागू की गई है।

- **सेवाएँ:** ऑनलाइन पंजीकरण, वीज़ा विस्तार, और विदेशी नागरिकों की ट्रैकिंग
- **प्रभाव:** राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि, सुव्यवस्थित प्रक्रिया, और विदेशी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मुलाक़ातों में कमी

मनरेगासॉफ्ट

मनरेगासॉफ्ट प्लेटफ़ॉर्म राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के पूर्ण डिजिटलीकरण को सक्षम बनाता है।

- **कवरेज:** सभी 33 ज़िलों में लागू
- **प्रभाव:** 32.5 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड जारी किए गए और 4.7 करोड़ मज़दूरी भुगतान लेनदेन डीबीटी के माध्यम से संसाधित किए गए, जिससे श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

छत्तीसगढ़, पी.एम.ए.वाई.-जी. के अंतर्गत आवास वितरण की निगरानी के लिए आवाससॉफ्ट और आवासऐप का उपयोग करता है।

- **कवरेज:** लाभार्थी चयन, आवास निर्माण और धन वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग
- **प्रभाव:** पारदर्शी निगरानी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के साथ ग्रामीण परिवारों के लिए 11 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए

ई-प्रोक्योरमेंट (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल)

सी.पी.पी.पी. प्लेटफ़ॉर्म को छत्तीसगढ़ में संचालित केंद्रीय संस्थानों और उद्यमों द्वारा अपनाया गया है।

- **उपयोगकर्ता:** एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई, एनटीपीसी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.), और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएँ
- **लाभ:** सरकारी खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही और खुली प्रतिस्पर्धा लाता है

अन्य शासन एवं नागरिक सेवाएँ

प्रमुख पहलों के साथ-साथ, छत्तीसगढ़ ने कई सहायक आईसीटी प्लेटफ़ॉर्म लागू किए हैं जो शासन, नागरिक सेवाओं और विभागीय दक्षता को विभिन्न क्षेत्रों में मज़बूत बनाते हैं।

शासन एवं न्याय

- **रेवकेस ऐप:** राजस्व न्यायालयों के लिए मोबाइल-सक्षम केस ट्रैकिंग और स्थगन प्रणाली, एसएमएस अलर्ट और डिजिटल ऑर्डर शीट के साथ
- **कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम (सी.सी.एम.एस.):** उच्च न्यायालय में सरकारी मामलों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत संग्रह; विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड और अनुपालन ट्रैकिंग
- **विधानसभा प्रणाली (ई-प्रश्न, ई-उत्तर, ई-प्रश्नोत्तरी):** प्रश्न प्रस्तुत करने, उत्तर देने और विधायी दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, विधानसभा कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाते हैं
- **लोक शिकायत पोर्टल:** मुख्यमंत्री कार्यालय, जन शिकायत और राज्यपाल कार्यालय के लिए एकीकृत शिकायत प्रणाली, रीयल-टाइम ट्रैकिंग और पारदर्शी समाधान के साथ

वित्त एवं कोषागार

- **आभार (ई-पेंशन) और ईकोश लाइट:** पारदर्शिता और दक्षता के लिए पेंशन वितरण और कोषागार भुगतान का डिजिटलीकरण
- **आई.एफ.एम.आई.एस. और एसएनए स्पर्श:** एकीकृत वित्त प्रबंधन प्रणाली जो सीएसएस और राज्य योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करती है डीबीटी से जुड़े भुगतानों के साथ
- **ई-चालान और ई-वाउचर:** इलेक्ट्रॉनिक रसीद और व्यय प्रणालियाँ आरबीआई ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत

वाणिज्य एवं उद्योग

- **उद्यम आकांक्षा पोर्टल:** एम.एस.एम.ई. और उद्योगों के लिए एकल-खिड़की पंजीकरण, सीएएफ जनरेशन और क्यूआर-कोडेड डिजिटल प्रमाणपत्रों के साथ
- **एकल-खिड़की प्रणाली:** विभिन्न विभागों में अनुमोदन के लिए एक ही आवेदन पत्र, व्यापार करने में आसानी को सक्षम बनाता है
- **फर्म और सोसायटी पोर्टल:** फर्मों और सोसायटी के पंजीकरण और संशोधन के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया, क्यूआर-कोडेड प्रमाणपत्रों के साथ
- **बॉयलर निरीक्षणालय पोर्टल:** बॉयलरों का ऑनलाइन पंजीकरण, नवीनीकरण और निरीक्षण, एकीकृत शुल्क भुगतान और तृतीय-पक्ष सत्यापन के साथ

ये पहल मिलकर प्रमुख परियोजनाओं का पूरक हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय वितरण, शिकायत निवारण, वित्तीय सुधार और औद्योगिक विकास मजबूत डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा समर्थित हैं - व्यापक डिजिटल शासन में अग्रणी के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा को मजबूत करते हैं।

मोबाइल ऐप्स

सीजी वीएचएसएनडी ऐप

सीजी वीएचएसएनडी ऐप स्वास्थ्य विभाग को आँगनवाड़ी और

शहरी-वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य, प्रारंभिक बचपन विकास, पोषण और स्वच्छता सेवाओं की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। भविष्य में आसान पहुँच के लिए उपयोगकर्ता अपनी एचआरएमआईएस आईडी के साथ एक बार लॉगिन करके एक एमपीआईएन जनरेट करते हैं। स्वास्थ्य सचिव और निदेशक के लिए राज्य-स्तरीय लॉगिन वीएचएसएनडी डेटा की केंद्रीकृत निगरानी और विश्लेषण का समर्थन करते हैं।

छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप

माननीय उप मुख्यमंत्री डॉ. विजय शर्मा द्वारा 14 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप बेरोजगार युवाओं को सीधे अपने मोबाइल फोन से रोजगार सहायता के लिए पंजीकरण करने में सक्षम बनाता है। त्वरित और सुरक्षित पंजीकरण के लिए आधार ओटीपी आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाता है।

यह नया पंजीकरण, नवीनीकरण और रिक्ति जानकारी को सुविधाजनक बनाता है, जिससे किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ताओं को उनका पंजीकरण संख्या, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग ई-रोजगार पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए भी किया जा सकता है।

जॉब चाहने वाले ऐप के माध्यम से राज्य और जिला-स्तरीय रोजगार मेलों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

अन्य मोबाइल ऐप्स

आई.जी.एम.आई.एस. (एकीकृत शिकायत एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली) परियोजना के अंतर्गत, एनआईसी छत्तीसगढ़ ने किसान- और छात्र-केंद्रित मोबाइल एप्लिकेशन का एक समूह विकसित किया है, जो आवश्यक सेवाओं को सीधे स्मार्टफ़ोन पर उपलब्ध कराता है।

प्रमुख ऐप्स:

- **क्रॉप डॉक्टर:** कीटों, रोगों और पोषक तत्वों की कमी की छवि-आधारित पहचान के लिए एआई-सक्षम ऐप, ऑनलाइन विशेषज्ञ सलाह के साथ। समय पर फसल प्रबंधन के लिए किसानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
- **ई-कृषि पाठशाला:** एक डिजिटल कक्षा जो कृषि छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री, वीडियो व्याख्यान, असाइनमेंट और ऑनलाइन परीक्षाएँ प्रदान करती है। 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड के साथ, यह मोबाइल पर एक वर्चुअल विश्वविद्यालय बन गया है
- **ई-हाट:** एक मार्केटप्लेस ऐप जो बिचौलियों पर निर्भरता कम करके किसानों को उत्पाद बेचने के लिए सीधे खरीदारों से जोड़ता है
- **कस्टम हायरिंग ऐप:** कृषि मशीनरी की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है

जिससे किसान स्थानीय स्तर पर उपकरण किराए पर ले सकते हैं और मशीनीकरण में सुधार कर सकते हैं।

प्रभाव (2025):

- किसान-केंद्रित ऐप्स में 1.35 लाख से ज़्यादा डाउनलोड
- फसल प्रबंधन, शिक्षा, विपणन और कृषि मशीनरी तक पहुँच में किसानों को सीधा लाभ
- कृषि सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ी और लागत कम हुई

सलाह, शिक्षा, विपणन और मशीनीकरण सहायता को एकीकृत करके, इन मोबाइल ऐप्स ने किसानों और छात्रों को सशक्त बनाया है, जिससे छत्तीसगढ़ डिजिटल कृषि और कृषि-शिक्षा सेवाओं में अग्रणी बन गया है।

▲ चित्र 2.3 : एनआईसी, छत्तीसगढ़ के ई-मानचित्र विज्ञान को सीएसआई मान्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ

नेटवर्क और बुनियादी ढाँचा

छत्तीसगढ़ में निकनेट, एनकेएन और उन्नत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के माध्यम से एक मज़बूत डिजिटल ढांचा स्थापित किया गया है, जिससे शासन, शिक्षा, अनुसंधान और न्याय वितरण के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है।

निकनेट और एनकेएन

- **ज़िला कनेक्टिविटी:** सभी 27 ज़िले 34 एम.बी.पी.एस./100 एम.बी.पी.एस. बी.एस.एन.एल. लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, छह ज़िलों में 1 जी.बी.पी.एस. रेलटेल बैकअप लिंक के साथ
- **कोषागार और विभाग:** एम.पी.एल.एस. लाइनें 67 कोषागारों/उप-कोषागारों और 13 राज्य पेय पदार्थ निगम स्थानों को सुरक्षित लेनदेन के लिए समर्थन प्रदान करती हैं
- **न्यायपालिका और शिक्षा:** लीज़्ड लाइन कनेक्टिविटी 88 न्यायालय परिसरों, 36 विश्वविद्यालयों और संस्थानों और राज्य मुख्यालयों को प्रदान की गई है
- **कोर बैकबोन:** नेटवर्क बैकबोन पी.जी.सी.आई.एल., बी.एस.एन.एल. और रेलटेल से 10 जी.बी.पी.एस. लिंक को एकीकृत करता है, जो उच्च गति और लचीली कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है
- **स्वान एकीकरण:** 25 ज़िलों से जुड़ा है, जो राज्यव्यापी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को और मज़बूत करता है

यह बुनियादी ढाँचा सुरक्षित सरकारी संचार, उन्नत अनुसंधान और ई-गवर्नेंस सेवाओं की डिलीवरी में सुधार, जिससे छत्तीसगढ़ देशव्यापी हाई-स्पीड डिजिटल ग्रिड का हिस्सा बन गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ

एनआईसी का अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्लेटफ़ॉर्म छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण बन गया है।

- **उपयोग:** 2019-2025 के बीच 3.5 लाख से ज़्यादा वीसी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षाएं, नीति आयोग परामर्श, विभागीय समीक्षाएं और न्यायिक सुनवाई शामिल थीं
- **न्यायपालिका:** न्यायालय परिसर जेलों और अन्य स्थानों से मामलों की सुनवाई के लिए वीसी का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जिससे देरी और लागत कम होती है
- **मान्यता:** राज्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए पूर्वी क्षेत्र (2025) में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया

उच्च गति वाले नेटवर्क और उन्नत वीसी सेवाओं के संयोजन ने छत्तीसगढ़ को एक डिजिटल रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया है, जिससे वास्तविक समय में निर्णय लेने, बेहतर सेवा वितरण और शासन तक समावेशी पहुँच संभव हुई है।

पुरस्कार और सम्मान

छत्तीसगढ़ की आईसीटी-आधारित पहलों ने कृषि, शिक्षा, शासन और आईसीटी अवसंरचना के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।

प्रमुख पुरस्कार:

- **2025** - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्कृष्टता: उत्कृष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के लिए पूर्वी क्षेत्र का प्रथम पुरस्कार; 3.5 लाख से अधिक सत्रों ने शासन समीक्षा, न्यायिक कार्यवाही और राष्ट्रीय परामर्श को सुगम बनाया
- **2023 – राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार:** क्रॉप डॉक्टर ऐप (आई.जी.के.वी., रायपुर) के लिए, जो एआई- आधारित फसल निदान और किसान सलाह को सक्षम बनाता है
- **2023 – एमबिलियनथ पुरस्कार:** एआई-संचालित स्कूल मूल्यांकन उपकरण, निकलर के लिए
- **2022 – सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस पुरस्कार:** टेलीप्रैक्टिस और ई-मानचित्र विज्ञान (भू-कृषि निगरानी) के लिए
- **2022 – आईएमसी डिजिटल पुरस्कार:** ई-प्रश्न और ई-उत्तर, विधायी प्रश्न प्रबंधन व विधानसभा की डिजिटल प्रणाली के लिए
- **2022 – डिजिटल प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार:** पीएमएस पोर्टल (पेंशन प्रबंधन) और सी.एस.ई.आर.सी. ई-याचिका प्रणाली के लिए

ये मान्यताएँ डिजिटल शासन में अग्रणी के रूप में छत्तीसगढ़ की भूमिका की पुष्टि करती हैं, जो कृषि, शिक्षा, विधायिका और बुनियादी ढाँचे में नवाचारों को आगे बढ़ा रही है।

अग्रिम दिशा

एनआईसी छत्तीसगढ़ डिजिटल शासन को गति दे रहा है। इसमें भूमि और वित्त प्रणालियों को सुव्यवस्थित करना, कृषि सेवाओं को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण करना और स्कूलों में ई-लर्निंग का विस्तार करना शामिल है। यह बेहतर शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म, डिजिटल हस्ताक्षर और डेटा-संचालित निर्णय लेने के माध्यम से नागरिक सेवाओं को भी बढ़ा रहा है—जिससे एक सहज, समावेशी, नागरिक-केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हो रहा है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी छत्तीसगढ़ राज्य केंद्र
14,15,16 प्रशासनिक खंड, द्वितीय तल, महानदी भवन
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492002
ईमेल: sio-cg@nic.in फ़ोन: 0771-2221238